

प्रारंभिक परीक्षा

खुदरा मुद्रास्फीति(Retail Inflation)

संदर्भ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर लगभग छह वर्ष के निम्नतम स्तर 3.16% पर आ गई, जो मार्च में 3.34% थी।

खुदरा मुद्रास्फीति (CPI-आधारित मुद्रास्फीति) से क्या अभिप्राय है?

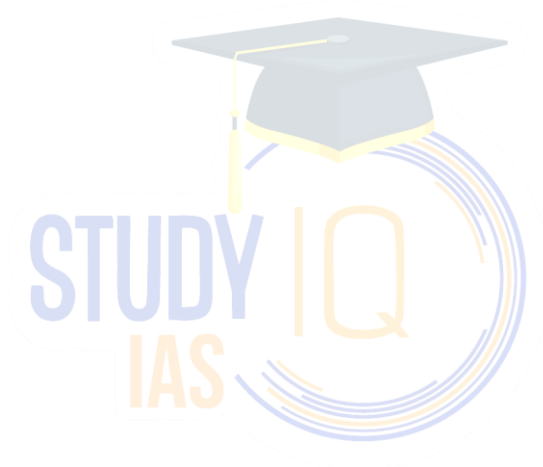
- खुदरा मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक निश्चित समयावधि में खुदरा स्तर पर परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं।
- इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापा जाता है -
 - CPI आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, शिक्षा आदि की एक निश्चित टोकरी में मूल्य परिवर्तन पर नज़र रखता है।
 - जब कीमतें बढ़ती हैं तो यह मुद्रास्फीति(inflation) का संकेत है।
 - जब कीमतें गिरती हैं तो यह अपस्फीति(deflation) का संकेत है।
- खुदरा मुद्रास्फीति (CPI-आधारित मुद्रास्फीति) के उपयोग -
 - नीतिगत निर्णय लेना (मौद्रिक नीति): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरें निर्धारित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों का उपयोग करता है।
 - मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: सरकार और आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के तहत CPI को आधिकारिक मुद्रास्फीति लक्ष्य मीट्रिक (वर्तमान में $4\% \pm 2\%$) के रूप में उपयोग करते हैं।
 - वेतन और पेंशन समायोजन: CPI का उपयोग बढ़ती कीमतों के मुकाबले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वास्तविक आय को बनाए रखने के लिए वेतन, मजदूरी और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है।
 - जीवन-यापन की लागत को मापना: CPI जीवन-यापन की लागत और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को दर्शाता है, जिससे यह आर्थिक कल्याण को समझने के लिए उपयोगी है।
 - राष्ट्रीय लेखा में अपस्फीतिकारक के रूप में: CPI का उपयोग नाममात्र मूल्यों को वास्तविक मूल्यों (जैसे, वास्तविक जीडीपी) में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिससे आर्थिक विकास के आंकड़ों से मुद्रास्फीति के प्रभाव को अलग करने में मदद मिलती है।
 - आर्थिक स्वास्थ्य संकेतक: यह अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, जो यह बताता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है या सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

WPI और CPI के बीच अंतर -

विशेषता	थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
परिभाषा	वस्तुओं और सेवाओं के लिए थोक स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।	उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए खुदरा स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
द्वारा जारी	आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

कवरेज	इसमें मुख्य रूप से केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, तथा विनिर्माण इनपुट और मध्यवर्ती वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।	इसमें खाद्य, आवास, परिवहन और चिकित्सा देखभाल सहित वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है।
आधार वर्ष	2011-12	2012

स्रोत: [The Hindu: Retail Inflation falls to 3.16, lowest level in 69 months](#)



विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025(World Bank Land Conference 2025)

संदर्भ

विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन, डीसी में आयोजित किया गया।

सम्मेलन के बारे में -

- यह नीतिगत निहितार्थों के साथ अनुसंधान प्रस्तुत करने, तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह सम्मेलन क्रॉस-सेक्टर सहयोग को भी बढ़ावा देता है और कई प्रमुख पहलों, निवेशों और अनुसंधान प्रयासों के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है - जिसमें काश्तकारी के जिम्मेदार शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश (वीजीजीटी), भूमि शासन मूल्यांकन ढांचा और स्टैंड फॉर हर लैंड अभियान शामिल हैं।
- 2025 में, सम्मेलन का विषय जागरूकता से लेकर कार्रवाई तक और भूमि काश्तकारी को सुरक्षित करने के बारे में है।

सम्मेलन में भारत का रुख -

- भारत ने अपनी दो प्रमुख पहलों - स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म - को भूमि प्रबंधन में नवाचार और मापनीयता के वैश्विक मॉडल के रूप में उजागर करके समावेशी, प्रौद्योगिकी-आधारित ग्रामीण शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

स्वामित्व/SVAMITVA (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) योजना

- ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण का उपयोग करके ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करता है।
- यह ग्रामीण नागरिकों को भूमि स्वामित्व से सशक्त बनाता है, ऋण तक पहुंच में सुधार करता है, तथा विवादों के बेहतर समाधान में मदद करता है।

ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म -

- ग्राम पंचायतों के लिए भू-स्थानिक नियोजन उपकरण।
- प्रभावी और जलवायु-लचीला विकास योजनाएँ बनाने के लिए स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा को एकीकृत करने में मदद करता है।
- ग्राम स्तर पर साक्ष्य-आधारित शासन को बढ़ावा देता है।

स्रोत: [PIB: World Bank Land Conference 2025 concludes](#)

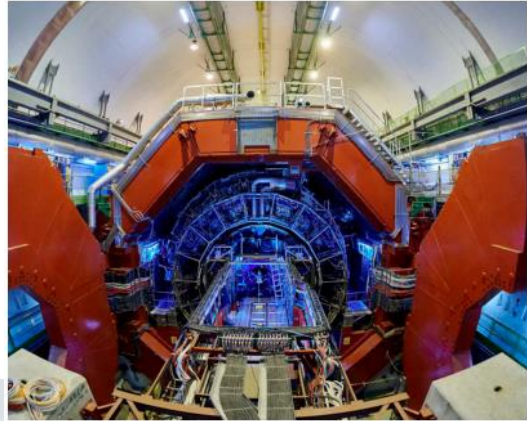
सर्न लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)

संदर्भ

एक नए अध्ययन में, यूरोप में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर(LHC) के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे कुछ ही सेकंड में सीसे के परमाणुओं को सोने के परमाणुओं में बदल सकते हैं।

सर्न LHC के बारे में -

- LHC(लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर) अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है।
- इसे 27 किलोमीटर लंबी गोलाकार सुरंग के रूप में बनाया गया है, जो कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट और विभिन्न त्वरक संरचनाओं से सुसज्जित है।
- LHC के अंदर, उच्च-ऊर्जा कणों (जैसे प्रोटॉन) की दो किरणें(**beams**) प्रकाश की गति के करीब की गति से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं।
- इन किरणों(**beams**) को अंततः टकराने के लिए बनाया जाता है, जिससे वैज्ञानिक इन टकरावों के परिणामों का विश्लेषण करके मौलिक कणों और बलों का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं।



The ALICE detector, which researchers used to track near-miss collisions between lead nuclei in the LHC. CERN

कण त्वरक(Particle Accelerator) क्या है?

- कण त्वरक एक वैज्ञानिक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करके आवेशित कणों (जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन) को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाता है और उन्हें एक विशिष्ट पथ पर ले जाता है।
 - इसका उपयोग कणों को आपस में टकराकर तथा परिणामी अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करके पदार्थ के मूल निर्माण खंडों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
 - कण त्वरक परमाणु भौतिकी, चिकित्सा चिकित्सा और पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: [The Hindu: Gold, as usual at great cost](#)

जूट की फसल

संदर्भ

भारतीय जूट निगम (JCI) ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसानों द्वारा फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए जूट के MSP (न्यूनतम विक्रय मूल्य) में वृद्धि की है।

जूट की फसल के बारे में -

- इसे लोकप्रिय रूप से "गोल्डन फाइबर" के नाम से जाना जाता है।
- यह एक "नकदी फसल" है।
- मिट्टी की आवश्यकताएँ: जलोढ़ या दोमट मिट्टी।
- फसल का प्रकार और जलवायु -
 - प्रकार: खरीफ फसल (मानसून ऋतु में बोई जाने वाली)
 - तापमान: आदर्श सीमा 25-35°C है
 - वर्षा: 150-250 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है
 - आर्द्रता: 80-90% सापेक्ष आर्द्रता में पनपता है
- भारत की वैश्विक स्थिति: भारत जूट उत्पादक देश में अग्रणी है, जो विश्व जूट उत्पादन में 70% का योगदान देता है।
- प्रमुख उत्पादक राज्य:
 - पश्चिम बंगाल: भारत के जूट उत्पादन में लगभग 75% का योगदान देता है
 - अन्य प्रमुख राज्य: बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय



स्रोत: [The Hindu: JCI increases MSP of Jute to stop distress selling of crop](#)

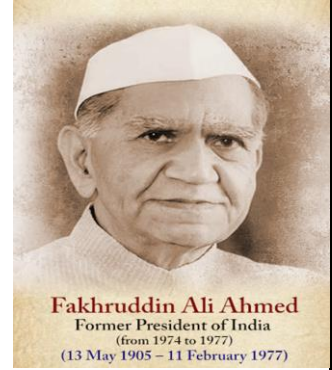
समाचार संक्षेप में

फखरुद्दीन अली अहमद

समाचार? हाल ही में राष्ट्रपति भवन में फखरुद्दीन अली अहमद की 121वीं जयंती मनाई गई।

📖 फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में -

- **जन्म:** 13 मई, 1905
- **कार्यकाल:** 24 अगस्त, 1974 – 11 फरवरी, 1977 (स्वतंत्र भारत के 5वें राष्ट्रपति)
- **मृत्यु:** 11 फरवरी 1977, पद पर रहते हुए।
- **महत्व:** डॉ. जाकिर हुसैन के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे मुस्लिम।
 - 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई।



संबंधित तथ्य -

- **भारत में आपातकालीन प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 352:** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातस्थिति की घोषणा।
 - **अनुच्छेद 356:** राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)।
 - **अनुच्छेद 360:** वित्तीय आपातकाल।
- **राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई:**
 - डॉ. जाकिर हुसैन- तीसरे राष्ट्रपति (1969)।
 - फखरुद्दीन अली अहमद (1977)।

मेअरिम नदी और ज्वारीय बोर

समाचार? मेअरिम नदी पर पोरोरोका ज्वारीय बोर लहर देखी गई।

🌊 ज्वारीय बोर(Tidal Bore) क्या है?

- ज्वारीय बोर एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें एक मजबूत ज्वार एक नदी या संकीर्ण खाड़ी को ऊपर धकेलता है, जिससे पानी का अचानक उछाल पैदा होता है जो नदी के प्रवाह की दिशा के विपरीत चलता है।
- यह अक्सर ऊपर की ओर बहती हुई पानी की दीवार या लहर के रूप में दिखाई देता है।

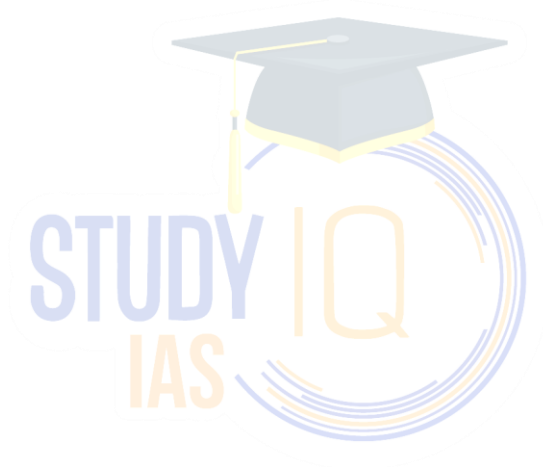


तथ्य -

- मेअरिम नदी उत्तरी ब्राज़ील के मरनहाओ राज्य में स्थित है।

भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई विदेश मंत्री बनीं

- प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा नियुक्त किया गया।
- ओकविले ईस्ट के लिए संसद सदस्य (MP) (2025-वर्तमान); इससे पहले ओकविले के लिए सांसद (2019-2025)।
- कनाडा के संघीय मंत्रिमंडल में सेवा करने वाले पहले हिंदू (2019)।
- विगत कैबिनेट भूमिकाएँ:
 - सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री (कनाडा की COVID-19 वैक्सीन खरीद की देखरेख)।
 - राष्ट्रीय रक्षा मंत्री (विशेष रूप से सैन्य यौन दुराचार संकट का प्रबंधन)।
 - ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष
 - परिवहन एवं आंतरिक व्यापार मंत्री



समाचार में स्थान

आदमपुर एयरबेस

खबर? पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की।



- अवस्थिति: पंजाब
- भारतीय वायु सेना का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस।
- सैन्य और सीमित नागरिक (घरेलू हवाई अड्डे) दोनों परिचालनों में कार्य करता है।

संपादकीय सारांश

भारत का डेयरी विरोधाभास

संदर्भ

रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिकी डेयरी के विरुद्ध जवाबी टैरिफ लगाने से भारत के लिए अवसर पैदा हो सकता है।

भारत के लिए अवसर -

- **अमेरिकी डेयरी पर जवाबी टैरिफ:** चीन जैसे देशों द्वारा अमेरिकी डेयरी निर्यात पर टैरिफ लगाने से वैश्विक बाजारों में अस्थायी शून्यता पैदा हो जाती है, जिसका भारत संभावित रूप से लाभ उठा सकता है।
- **विशाल घरेलू उत्पादन आधार:** भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक (240 मिलियन टन/वर्ष) है, जिससे इसे पर्याप्त कच्चा माल आधार प्राप्त है।
- **क्षेत्रीय बाजारों में मौजूदा उपस्थिति:** भारत पहले से ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात करता है, जिसे और मजबूत किया जा सकता है।
- **निकटता लाभ:** सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता भारत को कुछ एशियाई और खाड़ी बाजारों में स्वाभाविक बढ़त प्रदान करती है।

भारतीय डेयरी निर्यात के समक्ष चुनौतियाँ -

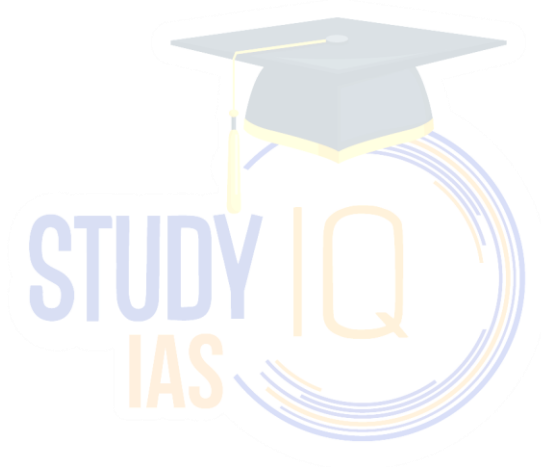
- **उत्पाद संरचना का बेमेल होना:** भारत मक्खन और दूध वसा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वैश्विक बाजार पनीर, मट्ठा प्रोटीन और कार्यात्मक डेयरी उत्पादों की मांग करते हैं - ऐसे क्षेत्र जहां भारत की क्षमता में कमी है।
- **अस्थिर एवं असंगत निर्यात प्रवृत्तियाँ:** स्किमड मिल्क पाउडर (एसएमपी) जैसे उत्पादों के निर्यात पैटर्न अस्थिर हैं, जो सतत प्रतिस्पर्धात्मकता के अभाव को दर्शाता है।
- **उत्पादन की उच्च लागत:** आईएफसीएन के अनुसार, भारत की दूध उत्पादन लागत (\$50-60 प्रति 100 किग्रा एससीएम) अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है।
- **कमजोर बुनियादी ढांचा:** खराब प्रसंस्करण क्षमता, सीमित कोल्ड चेन और उच्च रसद लागत भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती है।
- **विनियामक और गुणवत्ता संबंधी बाधाएं:** भारत अवशेषों और चारा गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।
 - उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने अभी तक भारत की अवशेष निगरानी योजना (आरएमपी) को मंजूरी नहीं दी है।
- **उत्पाद विविधीकरण और नवाचार का अभाव:** भारत ने कार्यात्मक डेयरी, पनीर और मट्ठा आधारित उत्पादों जैसे मूल्यवर्धित डेयरी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश नहीं किया है।
- **सीमित वैश्विक बाजार पहुंच:** यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, भारत में प्रमुख डेयरी आयातकों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का अभाव है।

आगे की राह -

- **मूल्य-संवर्धित उत्पाद श्रृंखलाओं में निवेश करना:** पनीर की किस्मों, मट्ठा प्रोटीन और कार्यात्मक डेयरी अवयवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करें जो वैश्विक मांग के अनुरूप हों।
- **बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** लागत प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए दूध प्रसंस्करण क्षमता, शीत श्रृंखला और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना।
- **उत्पादन लागत में कमी:** बेहतर प्रजनन, चारा प्रबंधन, तथा प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से डेयरी फार्म की उत्पादकता में सुधार लाकर इकाई लागत में कमी लाना।
- **वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना:** खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करें, यूरोपीय संघ आरएमपी अनुमोदन प्राप्त करें, और अंतर्राष्ट्रीय अवशेष और संदूषक मानदंडों का अनुपालन करना।

- **निर्यातान्मुख अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** विपणन योग्य डेयरी नवाचारों, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी और उत्पाद शेल्फ-लाइफ वृद्धि पर केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- **बाजार पहुंच पर बातचीत:** प्रमुख डेयरी आयातकों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते करना तथा कूटनीति के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रोत्साहन:** डेयरी प्रसंस्करण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और डेयरी निर्यात पर केंद्रित स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: [Economic Times: What Bharat, the world's top milk producer, must do as Trump tariffs open a window](#)



शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार: एक राष्ट्रीय विरोधाभास

संदर्भ

भारत की शिक्षा प्रणाली आकार बदलने वाले बाजार, अर्थात् कार्यबल के रूप में हमारे स्नातकों की रोजगार-क्षमता के मामले में पीछे रह गई।

भारत की शिक्षा प्रणाली रोजगारपरकता में क्यों पीछे रह गई?

- **शिक्षा और बाजार की जरूरतों के बीच बेमेल:** डिग्री में व्यावहारिक, नौकरी-उन्मुख कौशल का अभाव होता है।
 - व्यापकता और गहराई एकीकृत नहीं है - तकनीकी ज्ञान उथला है और गतिशील अर्थव्यवस्था में अनुकूलनशीलता का अभाव है।
- **निम्न स्नातक रोजगार क्षमता:** रोजगार क्षमता दर ~42-44% पर स्थिर हो जाती है।
 - ज्ञान-प्रधान रोजगार अत्यंत कम (~11.72%) बना हुआ है।
- **सुधारों के लिए दिखावटी वादा:** एनईपी 2020 में लचीले पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कई प्रवेश-निकास बिंदुओं का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कार्यान्वयन खराब या नाममात्र का रहा है।
 - सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए संरचित कार्यप्रणाली के अभाव ने नीतियों को अप्रभावी बना दिया है।
- **पुराने पड़ चुके विनियामक संस्थान:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियंत्रण का एक साधन बना हुआ है, जिसके विनियमनों के कारण बेहतर शिक्षण परिणामों या रोजगार-क्षमता का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है।
- **उद्योग से सम्पर्क का अभाव:** एनईपी मसौदा समिति में उद्योग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जो रोजगार की वास्तविकताओं से अलगाव को दर्शाता है।
 - पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु प्रायः पुरानी होती है तथा उसमें उद्योग प्रासंगिकता का अभाव होता है।
- **सतही स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र:** भारतीय स्टार्ट-अप अक्सर कम तकनीक वाले क्षेत्रों (जैसे, खाद्य वितरण) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें मुख्य तकनीकी या वैज्ञानिक नवाचार का अभाव होता है।
 - स्वदेशी अनुसंधान में कम निवेश से नवाचार आधारित रोजगार सृजन में बाधा आती है।

क्या किया जाना चाहिए (आगे की राह) -

- **उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करना:** पाठ्यक्रमों और इंटर्नशिप के सह-विकास के लिए विश्वविद्यालयों और व्यवसायों के बीच संरचित साझेदारी बनाना।
 - पाठ्यक्रम डिजाइन और विश्वविद्यालय प्रशासन में उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करना।
- **डिग्री से कौशल पर ध्यान केन्द्रित करना:** वास्तविक समय कौशल मानदंडों के साथ परिणाम-आधारित शिक्षा को शामिल करना।
 - मिडिल स्कूल से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल और सॉफ्ट स्किल्स को एकीकृत करना।
- **विनियामक ढांचे में सुधार:** यूजीसी जैसे पुराने निकायों का पुनर्गठन या विघटन करना।
 - रोजगारपरकता परिणामों पर केन्द्रित स्वतंत्र मान्यता एवं मूल्यांकन एजेंसियां बनाना।
- **अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करना:** मुख्य प्रौद्योगिकी (एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक) में स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करना।
 - ऐप-आधारित सुविधा मॉडल के बजाय गहन तकनीक और विज्ञान-आधारित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और जवाबदेही में सुधार:** संकाय के लिए नियमित कौशल उन्नयन।
 - वित्त पोषण को मापनीय शैक्षणिक और रोजगारपरक परिणामों से जोड़ना।

- **सार्वजनिक परियोजनाओं की पारदर्शिता और मूल्यांकन सुनिश्चित करना:** न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई), इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईएमप्रींट) जैसी बड़ी परियोजनाओं के प्रभाव का लेखा-परीक्षण करना।
 - नवाचारों, पेटेंटों, स्टार्ट-अप्स और रोजगार सृजन पर परिणामों को सार्वजनिक रूप से साझा करना।
- **शिक्षा को आजीवन सीखने के रूप में पुनः परिभाषित करना:** मुक्त विश्वविद्यालयों, व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) और स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय-शिक्षण के अध्ययन जाल) जैसे डिजिटल कौशल विकास प्लेटफार्मों के माध्यम से सतत सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

NMITLI: नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल -

- 2000 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा शुरू किया गया
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाले अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को चुनिंदा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना।

IMPRINT: अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव -

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया
- **उद्देश्य:** अनुसंधान को व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करके भारत में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करना

स्रोत: [The Hindu: In India, education without employment](#)

